भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5312

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2019

एसएमई हेतु सार्वजनिक खरीद नीति

5312. श्री पी. वेलुसामीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 25 अप्रैल, 2012 को जारी आदेश के अनुसार लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति का ब्यौरा क्या है, जो यह कहती है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को एसएमई से कम से कम 20 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए और इसमें से 4 प्रतिशत अजा/अजजा द्वारा प्रवर्तित उद्यमों से होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए पीएसयूएस खरीद का कुल मूल्य कितना है;

(ग) अज/अजजा द्वारा प्रवर्तित उद्योगों/उद्यमों से खरीद का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को वाणिज्य और उद्योग के दलित चैम्बर से इस संबंध में कोई अनुरोध/शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त नीति के तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 अधिसूचित किया है। इस नीति के तहत केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएससी) द्वारा वार्षिक खरीद की 25 प्रतिशत खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जानी है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3 प्रतिशत की खरीद करना शामिल है।

(ख) और (ग) : संबंध पोर्टल पर 2017-18, 2018-19 और वर्तमान वर्ष में 22 जुलाई, 2019 तक अपलोड की गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएससी) द्वारा एमएसई से वस्तुओं एवं सेवाओं की वार्षिक खरीद जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद शामिल है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	सीपीएसई की संख्या (सूचित)	कुल खरीद (करोड़ रु. में)	एमएसई से खरीद (करोड़ रु. में)	अ.जा./अ.ज.जा. स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद (करोड़ रु. में)
2017-18	170	114042.05	26357.46	544.72
2018-19	162	152620.40	40303.26	823.87
2019-20 (22 जुलाई, 2019 तक)	77	22658.63	5631.38	100.38

(घ) : सरकार को समय-समय पर विभिन्न एमएसई और उद्योग संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और उनका नीति के प्रावधानों के अनुसार हल किया जाता है।

(ङ) : सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के कारगर मॉनीटरिंग के लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल लांच किया गया है।

*****